

कुछको चीन को विक्रीको बाटोहिए, यह इत लेखको में एम्बोई नहीं होता है, क्योंकि जो पूर्वोत्तर मंत्री का प्रधान मंत्री रहे चुके हैं, उन के ऊपर तो हाउस में रोज प्रांगेप लगते हैं। उन्होंने देश में एमर्जेंसी लगाई इस पर जो सवाल उठाया गया क्या किमी न नाटिम दिया बा ?

**MR. SPEAKER** I am not deciding that point

**डा० बलदेव प्रकाश** आप मरी बात सुन लीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जा पहले प्रधान मंत्री या मंत्री रह चुके हैं उन पर जो आरोप लगते हैं उस के बारे में आप का पहले से नाटिस देना आवश्यक नहीं है। यह तो केवल सरकार का भ्रन्दर जा आफिसर्स काम करत हैं उन के खिलाफ कार्ड एसीगेशन लगाना हा ता नाटिस की जरूरत हाती है

**MR. SPEAKER** I have not ruled that way uptill now

**डा० बलदेव प्रकाश** आप मेरी बात सुन लीजिए। आप ने उन का 10 मिनट दिये हैं मुझे दो मिनट भी देने का तैयार नहीं है। उन्होंने हर बात दस बार रिपीट की है, लेकिन मे रेपीटिशन नहीं कर रहा हूँ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिमला समझीते के बकल प्रखारो के द्वारा सारी जनता का पता है कि बातचीत टूट गई थी, बातचीत टूटने के बाद भतपूर्व प्रधान मंत्री और श्री मुट्टो रात को मिले तो अगर कोई मूल बात नहीं हुई थी ता वे किस लिए मिले थे—यह हाउस के सामने बतलाया जाय। मिलने के बाद क्या फैसला हुआ—यह बात किसी के सामने नहीं आई, लेकिन बकदम सौध पर दस्तखत किये गये, इस का मतलब है कि कुछ न कुछ तो फैसला हुआ होगा। प्रखारो में छप चुका था कि बातचीत टूट गई, उस के बाद रात को दो बजे मुलाकात हुई और बकदम सुबह दस्तखत हो गये—यह

विष्ट यह पता नहीं कि बाटोहिए कि कहीं पर क्या बात हुई थी और उस समझीते के मुताबिक जो बातें हुई थी, वे स्पष्ट होनी चाहिए।

**MR. SPEAKER** Now, matters under Rule 377—Shri Tarun Gogoi.

13.24 hrs.

[**MR. DEPUTY-SPEAKER** in the Chair]

**MATTERS UNDER RULE 377**

(1) **REPORTED DECISION OF ONGC TO SLOW DOWN CRUDE PRODUCTION IN NORTH-EASTERN REGION**

**SHRI TARUN GOGOI** (Jorhat) By giving notice under Rule 377 I would like to draw the attention of the Minister of Petroleum and Chemicals to the reported decision of the Oil and Natural Gas Commission to slow down the crude production in the North-Eastern Region, particularly, in Assam. It has been a matter of great concern not only for the people of that region but to the whole nation to see this retrograde step of stepping down the production of crude oil when there are great prospects of increasing such production because of numerous deposits of oil reserves in Assam, Nagaland and Tripura

Besides, it raises an apprehension in the minds of the people of that region that the Centre is not interested in the development of that area by continuing its policy of neglect and apathy towards this region. While there is a great need to speed-up the crude production in order to move towards attaining self-sufficiency and all out efforts are being made to increase the production on the Bombay High, the slackening of such efforts in the North-Eastern region runs counter to the declared national policy on oil and the policy of removal of regional imbalances. It has been reported that due to the limited capacity of the existing refineries and the limited capacity of the pipelines such steps are

[Shri Tarun Gogoi]

taken. If so, O.N.G.C. are to be blamed squarely for not taking adequate steps before, inspite of its knowledge of known deposits of crude in that region.

This is not the first time that such a thing has happened earlier also in Assam the oil field of Naharkatia though was discovered in the year 1952, the wells were kept sealed till 1962 when the Gauhati Refineries came up. To avoid such complications in future, immediate steps should be taken and production in that region need not be stopped or slowed down by setting up a new refinery nearby the site of the reserves to meet all the requirements and thereby helping these backward regions to come up in the map of Petro-Chemical Industry in the country.

(1) REPORTED DIFFICULTIES FACED BY  
RAJKOT DIESEL OIL ENGINEERING  
INDUSTRY.

श्री धर्मेन्द्र जाई पटेल (राजकट )  
उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा के नियम 377 के अधीन लोक महत्त्व के निम्न दक्षिण विषय 'गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकट में बनते हुए डीजल ध्रायल इजनों' की क्वालिटी (क्यू) मार्क की मान्यता (रिकगनी-शन) उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक की धार से तारीख 1-4-78 से रह करने से राजकट डीजल इजीनियरिंग उद्योग पर बड़ा खतरा होने के बारे में मैं सक्षिप्त में बकनव्य देना चाहता हूँ।

गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश के राजकट शहर में ध्रायल इजीनियरिंग के उद्योग का विकास हुआ है। इस उद्योग में डीजल कुड ध्रायल इजन और इन के पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) बनाये जाते हैं। राजकट में 160 डीजल ध्रायल इजन उत्पादन करने की छोटी छोटी फैक्ट्रिया और डीजल इजन के पुर्जे बनाने की करीब 2000 छोटी छोटी फैक्ट्रिया हैं।

राजकट में वार्षिक करीब एक लाख डीजल इजन बनते हैं जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपये के होती है। इन में 20,000 मजदूर काम करते हैं। समूचे देश में 3 लाख ध्रायल इजन का उत्पादन होता है। इन में से राजकट में एक लाख डीजल इजनों का वार्षिक उत्पादन होता है। इसी तरह से देश के एक तिहाई हिस्सा का उत्पादन सिर्फ राजकट (सौराष्ट्र) में होता है।

राजकट में वार्षिक उत्पन्न हुए इस एक लाख डीजल इजनों में से करीब 30 हजार डीजल ध्रायल इजनों की उत्तर प्रदेश में बिक्री होती है और 20 000 इजन मध्य पूर्व और दूर पूर्व के दूसरे देशों में निर्यात होते हैं और बकाया देश के अन्दर राज्यों में बिक्रि जाते हैं।

इन डीजल ध्रायल इजनों की गुणवत्ता के लिए इण्डियन स्टैंडर्ड इस्टीमेशन से राजकट के 16 बड़े उत्पादकों ने आई एस आई के मार्क लिए है। आई एस आई मार्क लेने के लिए करीब एक लाख रुपये की मशीनरी लगानी पडती है। यह छोटे उद्योग वाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुजरात और अन्य सरकारों ने आई एस आई जैसे 'क्यू' मार्क को पद्धति अपनाई है। इनमें केवल छोटे उद्योग वालों को 20 हजार रुपये का खर्चा करना पडता है। और गुजरात में ऐसी यंत्रियों के क्यू मार्क के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक ने राजकट में बनते हुए यह क्यू मार्क वाले डीजल इजनों की मान्यता ता० 1-4-78 से बढ़ कर दी है। इससे राजकट के करीब 7,000 मजदूरों और छोटी फैक्ट्री वालों को कठिनाइया उत्पन्न हुई हैं।

राजकोट इजीनियरिंग एसोसिएशन राज-  
कोट ने ता० 22-3-78 से तार से भारत